राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. विविध आपराधिक जमानत आवेदन सं. 16336/2023

भाखर राम पुत्र कछभा राम, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी- विष्णु नगर, बावरला, पी. एस. सरवाना, जि. जालोर। (वर्तमान में जिला जेल जालोर में स्थित है।)-----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. लोक अभियोजक के माध्यम से, राजस्थान राज्य।

2. भजन लाल पुत्र कृष्ण राम, शेरोनियो की ढाणी, सिवाडा पी. एस. चितलवाना, जि. जालोर------ उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिएः- श्री धीरेंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सहायक सुश्री प्रियंका बोराना।

प्रत्यर्थी (ओं) के लिए:- श्री अरुण कुमार, लोक अभियोजक।

माननीय श्री जस्टिस फरजंद अली

आदेश

रिपोर्ट योग्य

12/02/2024

1. अभियुक्त-याचिकाकर्ता के कहने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत आवेदन दायर करके इस अदालत के क्षेत्राधिकार का उपयोग किया गया है। इस मामले के आवश्यक विवरण नीचे सारणीबद्ध किए गए हैंः-

क्रम संख्या	मामले का विवरण	
1.	एफ. आई. आर. संख्या	63/2023
2.	संबंधित पुलिस थाना	सरवाना
3.	जिला	जालौर

4.	एफ. आई. आर. मे दर्ज कथित अपराध	आई. पी. सी. की धारा 302/34 और 120-बी और शस्त्र अधिनियम 5 की धारा 3/25 में आरोपित अपराध
5.	अपराध जोड़े गए, यदि कोई हो	-----
6.	आक्षेपित आदेश पारित होने की तिथि	04.12.2023

2. अभियुक्त-याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई है कि उसके खिलाफ कथित अपराधों के लिए कोई मामला नहीं बनता है और उसे जेल में रखने की जरूरत नहीं है। मामले में ऐसा कोई भी कारक नहीं है जो आरोपी-याचिकाकर्ता को जमानत दिए जाने के खिलाफ काम कर सके और उसे संदेह और अनुमान के आधार पर आरोपी बनाया गया है। सह-आरोपी जगराम, गजारो और किरण को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों के विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामला जमानत पर आरोपी के छोड़े जाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

4. मैने दोनों पक्षों द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

5. एफ. आई. आर. के अवलोकन से पता चलता है कि दोनों पक्ष करीबी रिश्तेदार हैं और घटना से 4-5 साल पहले, सह-आरोपी किरण की शादी मोहन लाल के साथ की गई थी, जो मृतक भीखा राम का बेटा है और मृतक की बेटी की शादी गणपत लाल से हुई थी। कुछ वैवाहिक कलह के कारण, मृतक पक्ष के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 498-ए और 494/114 के तहत अपराधों के लिए एक आई. पी. आर. दर्ज की गई, जिसमें दो आरोपी मोहन लाल और मोहिनी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। यह दोनों परिवारों के बीच झगड़े का मूल कारण था। आरोप पत्र से यह पता चलता है कि घटना के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, यानी 02.07.2023 को, मृतक ने बुधराम, शांति लाल और बडगुराम सहित अन्य व्यक्तियों के साथ गाँव बावरला का दौरा किया, जहाँ आरोपी पक्ष एक सामुदायिक सभा में भाग लेने और कुछ प्रथागत अनुष्ठानों के प्रदर्शन के उद्देश्य से रहता है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे का सामना किया और तीखी नोकझोंक के

बाद, याचिकाकर्ता के बेटे प्रवीण ने भीखाराम पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता भी अपराध स्थल पर मौजूद था और यह दलील दी गई है कि यदि याचिकाकर्ता ने ही आरोपी प्रवीण को मृतक पर गोली चलाने के लिए उकसाया था तो उसे मृतक भीखाराम पर गोली चलाने से किसने रोका, क्योंकि ऐसा कोई अवसर नहीं था कि वह बंदूक खुद चलाने के बजाय अपने बेटे को दे देता।

6. प्रस्तुत किए गए तर्कों और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री पर विचार करने के बाद, यह महसूस किया गया कि बचाव पक्ष के तर्क में दम है कि दुश्मनी के कारण, मृतक भीखाराम की मौत के मामले में पूरे परिवार को शामिल किया गया है, जबकि तथ्य यह है कि यह आरोपी प्रवीण था जिसने मृतक पर बंदूक चलाई थी जिससे उसे गोली लगी थी।

7. मैंने अभियोजन पक्ष के गवाहों घामा राम, राम सिंह, रामजू राम, भजन लाल, आशू राम, जयकिशन, श्रवण कुमार, ओम प्रकाश, गणपत लाल, शांति लाल और भजन लाल पुत्र कृष्ण लाल के बयानों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और पाया है कि हालांकि सभी गवाहों ने स्पष्ट शब्दों में कहानी सुनाई है कि श्रीमती किरण चिल्लाई और अपने पिता (याचिकाकर्ता) से मृतक को मारने के लिए कहा जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने अपने बेटे प्रवीण को बंदूक दी और फिर प्रवीण ने मृतक को गोली मार दी, हालांकि गवाहों के सामान्य कथन और मनगढ़ंत पाठ ने इस न्यायालय को यह सोचने के लिए प्रेरित किया है कि यह एक ऐसा मामला हो सकता है जहां अकेले आरोपी प्रवीण जिम्मेदार था और पिछली दुश्मनी के कारण, पूरे परिवार को मामले में खींचा गया है। जाँच एजेंसी ने इस संबंध में सामग्री एकत्र की है और आरोप पत्र दायर किया गया है। अब, उपर्युक्त मुद्दे का पता विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों द्वारा ट्रायल में

साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद लगाया जाएगा और इसका परीक्षण प्रतिपरीक्षा और गवाहों की पुनः परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय इस संबंध में कोई प्रतिकूल राय देने से बचता है।

8. अब, जमानत पर विचार करने के एक अन्य पहलू पर आते हैं जहां पिछली दुश्मनी का दावा करते हुए गलत निहितार्थ की याचिका दायर की गई है। पिछली दुश्मनी एक दोधारी हथियार की तरह होती है; इसका एक पहलू यह है कि यह दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए आरोपी के लिए कार्रवाई के कारण को जन्म देता है; यह आरोपी को बदला लेने के लिए उकसाता है, हालांकि, इसका दूसरा पहलू यह है कि यह शिकायतकर्ता/अभियोजक को दुश्मन को झूठे मामले में खींचने के लिए समान संभावना प्रदान करता है ताकि उसे दंडित किया जा सके या सबक सिखाया जा सके। इस बात के दो दृष्टिकोण हैं कि कैसे एक आपराधिक मुकदमे के पक्ष एक-दूसरे के दुश्मन हैं, जब मामले की उत्पत्ति पहले से ही दोनों पक्षों के बीच बनी हुई है; यदि आरोपी पीड़ित का दुश्मन है तो पीड़ित भी आरोपी का समान रूप से दुश्मन है। जब ऐसे मामले जहां पूर्व कटुता की पृष्ठभूमि से संबंधित कोई मुद्दा निर्णय के लिए सामने आता है, तो यह स्पष्ट रूप से समझना मुश्किल होता है कि क्या आरोपी ने पीड़ित पर हमला किया या पीड़ित ने आरोपी को, जो उसका दुश्मन है, कीचड़ में घसीटा। इस प्रकार, न्यायाधीश के लिए इस पर निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी सुविचारित राय में, उपरोक्त जैसे मामलों में, पूरे साक्ष्य की बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिए ताकि एक गलत और अनुचित निर्णय के पारित होने को विफल किया जा सके।

9. सामान्यतः यह माना जा सकता है कि यदि कोई अभियुक्त पीड़ित के सामने खड़ा होकर अपने हाथ में बंदूक लिए हुए है और उनके बीच तीखी नोकझोंक हो रही है, तो अभियुक्त की स्वाभाविक

प्रवृत्ति दुश्मन पर निशाना साधकर गोली चलाने की होगी। इस मामले में, उपरोक्त आम आदमी या सामान्य भाषा की उपमा इस अदालत के दिमाग में आई है क्योंकि पिता और पुत्र दोनों घटना स्थल पर मौजूद थे और यह आरोप लगाया जाता है कि पिता (याचिकाकर्ता) ने पीड़ित को मारने के लिए बेटे को हथियार की आपूर्ति की थी। सामान्य विवेक में, यह माना जा सकता है कि पीड़ित को गोली मारने के लिए अपने बेटे को हथियार की आपूर्ति करने के बजाय, पिता स्वयं चाहते हैं और पीड़ित पर गोली चलाने और उसे अपने हाथों से मारने का विकल्प चुनते हैं क्योंकि एक प्यार करने वाला/दयालु पिता कभी भी अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने का विकल्प नहीं चुनता है और इसके बजाय, वह अपने कंधों पर दोष/जिम्मेदारी/परेशानी लेने का विकल्प चुनता है ताकि अपने बेटे को बचाया जा सके। हालाँकि यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी स्थिति हर समय एक ही तरीके से सामने आए, लेकिन यह ज्यादातर समय इस तरह से सामने आ सकती है। यह विशेष तथ्य कमजोर प्रतीत होता है और यह बहुत कम संभावना है कि एक गर्म वातावरण में, पिता दुश्मन को खुद गोली मारने का विकल्प नहीं चुनेंगे और इसके बजाय अपने बेटे को बंदूक सौंप देंगे और उसे पीड़ित/दुश्मन को गोली मारने का आदेश देंगे, खासकर जब वे एक-दूसरे के बगल में खड़े हों। सामान्य विवेक में, वह किसी और को हथियार की आपूर्ति करने में समय बर्बाद नहीं करेगा, अपने स्वयं के बच्चे की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि इस बीच, दुश्मन के पास खुद को बचाने या अनुमान/प्रत्याशा में हमला करने का मौका हो सकता है।

10. एक आपराधिक मामले पर निर्णय लेते समय, न्यायालयों को तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य को एक परिदृश्य की तरह एक विशाल दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है, यानी व्यापक, अखंड और सभी दिशाओं में। सरल शब्दों में, एक अपराध एक परिवेश में सामने

आता है और एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है और इस प्रकार, इरादे, एक उचित रूप से विवेकपूर्ण व्यक्ति का मनोविज्ञान, घटनाओं की सामान्य व्यापकता, अभियुक्त की परिस्थितियाँ, अभियुक्त व्यक्तियों का एक-दूसरे के साथ संबंध, आसपास के वातावरण में मौजूद उत्तेजक और कई अन्य पहलुओं जैसे कई चौकस कारकों पर जमानत देने के लिए एक मामले पर विचार करते समय विचार किया जाना चाहिए। बेशक, अभियुक्त की सजा की अवधि निर्धारित करते समय अभियुक्त की परिस्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। एक अभियुक्त के लिए विशिष्ट परिस्थितियाँ इस बात पर विचार करने के लिए प्रासंगिक हैं कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल कहां है, इस प्रकार, कुछ मामलों में जमानत देते समय थोड़ा गहरा गोता लगाना अप्रासंगिकता का अभ्यास नहीं है।

11. जबकि अदालतें उन मामलों के निर्धारण में लगी हुई हैं जहां अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 34,109,120-बी और 149 जैसे प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है, जहां कई अभियुक्त शामिल हैं और प्रत्यावर्ती दायित्व की अवधारणा भी सामने आती है, अदालतों को उचित सावधानी के साथ अभियुक्त के खिलाफ उपलब्ध पूरी सामग्री का आकलन और जांच करनी चाहिए ताकि स्पष्ट शब्दों में अभियुक्त की सटीक भूमिका को समझा जा सके। यह ऐसे मामलों में और भी अधिक अनिवार्य हो जाता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है क्योंकि इन मामलों में अति-प्रभाव सामान्य ज्ञान और चिंता की बात है। यह एक सामान्य घटना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, व्यक्तिगत द्वेष या शत्रुतापूर्ण संबंध रखने वाले व्यक्ति में कथित अपराध में मुख्य आरोपी से जुड़े अधिक संख्या में व्यक्तियों को फंसाने की प्रवृत्ति होगी, इसलिए जब भी मुद्दा साक्ष्य का आकलन करने के लिए आता है ताकि किसी आरोपी पर प्रत्यावर्ती दायित्व तय किया जा सके, तो अदालतों

को जमानत या गुण-दोष पर सवाल होने पर साक्ष्य पर गहन चर्चा और मूल्यांकन करने के लिए अधिक सतर्क रहना चाहिए।

12. इस न्यायालय का विचार है कि जमानत याचिका पर विचार करते समय, चाहे वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 या धारा 439 के तहत हो, अदालतों को सावधानीपूर्वक और गहराई से सामग्री पर विचार करना चाहिए यदि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, व्यक्तिगत द्वेष, प्रतिशोध आदि जैसी विशेषताएं शामिल हैं, जहां गलत, तुच्छ, आंशिक रूप से झूठे या आंशिक रूप से तुच्छ आरोपों के आधार पर विरोधी पक्ष को फंसाना या दोनों पक्षों के दुश्मन को चोट पहुंचाना मानवीय प्रवृत्ति है।

13. आपराधिक न्यायशास्त्र में एक ऐसी घटना प्रचलित है जिसके अनुसार यदि बचाव पक्ष की याचिका से यह प्रतीत होता है कि बरी होने की थोड़ी सी भी संभावना है, तो अदालतों को ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ देने की ओर झुकना चाहिए जैसे कि वह अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रहता है और उसकी दोषसिद्धि कायम नहीं रहती है, तो अदालतें उसे वे दिन वापस करने में असमर्थ होंगी जो वह पहले ही जेल में बिता चुका है और इस दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य को उलटने का कोई तरीका नहीं होगा। यहां यह याद रखना उचित है कि दंडादेश की अवधि के एक हिस्से को दोषसिद्धि से पहले के चरण में और इसके शेष हिस्से को दोषसिद्धि के बाद के चरण में दण्ड देने की कोई अवधारणा आपराधिक न्यायशास्त्र के साथ-साथ आपराधिक कानूनों में नहीं है जो भारत में लागू हैं।

14. यह लगभग तय कानून है कि दोषसिद्धि से पहले के चरण में; जमानत एक नियम है और उससे इनकार एक अपवाद होना चाहिए। मुकदमे के दौरान एक आरोपी को सलाखों के पीछे रखने के पीछे का उद्देश्य दोषसिद्धि के दिन उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना होगा ताकि वह सजा प्राप्त कर सके जैसा कि उसे दी जाएगी। अन्यथा,

यह आपराधिक न्यायशास्त्र का नियम है कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा।

15. आपराधिक प्रक्रिया संहिता में बनाए गए कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से प्रतिपादित कानून और जमानत न्यायशास्त्र पर विचार-विमर्श करने के बाद, यह समझा जाता है कि जमानत याचिका पर विचार करते समय एक अदालत को केवल एक चीज का पता लगाना होता है कि क्या आरोपी को अपने घर से न्यायिक कार्यवाही में भाग लेने के लिए अदालत में आने की अनुमति दी जानी चाहिए और उसे अपने परिवार के साथ और समाज के भीतर इस विशिष्ट शर्त पर रहने की अनुमति दी जानी चाहिए कि मामले की सुनवाई की निर्धारित तिथि पर वह जानबूझकर अदालत की कार्यवाही में भाग ले या इसके विपरीत, वह ऐसा व्यक्ति है जिसे लंबित मुकदमे में भी हिरासत में लिया जाना चाहिए और उसे अपने परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह तय किया जाना है कि क्या उसे अपने परिवार के साथ खाने, सोने और रहने की अनुमति दी जा सकती है जैसे कि एक आदमी सामान्य रूप से करता है या उसे खाने, सोने और जेल में रहने की अनुमति दी जा सकती है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या न्यायालय अभियुक्त को स्वतंत्र व्यक्ति (व्यक्तियों) के बांड और जमानत प्रस्तुत करने पर अपने घर से कार्यवाही में भाग लेने के लिए न्यायालय में आने की अनुमति देना चाहता है या न्यायालय सोचता है कि उसे स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए ताकि उसे सुनवाई के लिए निर्धारित दिन न्यायालय के समक्ष लाया जा सके। इस न्यायालय का विचार है कि यह उन प्रमुख चिंताओं में से एक है जिन पर विचार किया जाना चाहिए और जमानत याचिका पर विचार करते समय

इसका पता लगाया जाना चाहिए। यह वर्तमान युग में एक न्यायिक रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य है कि लंबित मामलों की अधिक मात्रा के कारण, मुकदमे की परिणति में काफी समय लगता है और मेरे विचार में, मामले के लंबित रहने के दौरान आरोपी को सलाखों के पीछे रखने से असाधारण परिस्थितियों के अलावा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

16. जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए अगला विचार यह होगा कि सह-अभियुक्त जगराम राम, श्रीमती गजरो और किरण को एस. बी. विविध आपराधिक जमानत आवेदन सं 12856/2023,9957/2023 और 10312/2023 मे पारित 07.11.2023 के आदेश के अनुसार इस अदालत द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

17. मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, निर्दोषता, झूठे निहितार्थ, अति-दोहन और अतिशयोक्ति की दलीलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि तत्काल कार्यवाही 60 वर्षीय व्यक्ति की स्वतंत्रता के सवाल से संबंधित है। अभियोजन पक्ष द्वारा 33 गवाहों को पेश किया गया है और यह माना जा सकता है कि मुकदमे को निश्चित रूप से एक वैध निष्कर्ष पर पहुंचने में लंबा समय लगेगा और याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए सलाखों के पीछे रखने का कोई उचित कारण नहीं दिखता है।

18. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप तथा समानता के आधार पर विचार करने के बाद, विशेष तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता वह व्यक्ति नहीं था जिसने मृतक पर गोली चलाई थी तथा तथ्य यह है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि मुकदमे को समाप्त होने में लंबा समय लग सकता है, यह न्यायालय वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ प्रदान करना उपयुक्त समझता है।

19. तदनुसार, धारा 439 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत तत्काल जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है और यह आदेश दिया जाता है कि कारण शीर्षक में नामित अभियुक्त-याचिकाकर्ता को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, बशर्ते कि वह सुनवाई की सभी तिथियों पर संबंधित अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए विद्वान विचारण न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए 50,000/- की राशि के साथ 25,000/- की दो प्रतिभूतियों के साथ एक व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करे।

(फरजंद अली), जे.

अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।